

[Mr. Speaker]

Rajkumari Amrit Kaur was a Member of the Constituent Assembly of India, the Provisional Parliament and the First Lok Sabha during the years 1946 to 1957. She was also Minister of Health during the years 1947 to 1957. She passed away at New Delhi on the 6th February, 1964 at the age of 75.

Thakur Raghuraj Singh was a Member of the Constituent Assembly of India during the years 1947 to 1948. He passed away at Raipur on the 5th February, 1964.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved families.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a short while.

12-20 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF THE RAILWAY ACCIDENTS COMMITTEE

The Minister of Railways (Shri Dasappa): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (i) Report of the Railway Accidents Committee 1962 (Part II)
- (ii) Summary of Observations and Recommendations contained in Part II of the Report of the Railway Accidents Committee 1962 and Railway Board's comments thereon.

[Placed in Library. See No. LT-2230/64].

NOTIFICATIONS REGARDING EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS SCHEME, 1963

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman): Sir, I beg to lay on the Table:—

- (i) a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 7 of the Employees' Provident Funds Act, 1952:—

(a) The Employees' Provident Funds (Twenty-first Amendment) Scheme, 1963, published in Notification No. G.S.R. 1845 dated the 28th November, 1963.

(b) The Employees' Provident Funds (Twentieth Amendment) Scheme, 1963, published in Notification No. G.S.R. 1873 dated the 7th December, 1963.

[Placed in Library. See No. LT-2231/64].

- (ii) S. O. 3324 dated the 28th November, 1963 issued under the Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1963.

[Placed in Library. See No. LT-2232/64].

12-21 hrs.

ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT, DISCHARGING THE FUNCTIONS OF THE PRESIDENT

Secretary: Sir, I lay on the Table a copy of the Address by the Vice-President, discharging the functions

of the President, to both Houses of Parliament assembled together this morning.

अभि-भाषण

उप-राष्ट्रपति : संसद के सदस्यगण, संसद के नए जलास का कार्यभार उठाने के लिए एक बार फिर मैं आग सबका स्वागत करता हूँ ।

२. अभी हाल ही में जो साल खत्म हुआ है उसमें भारत की सरकार और जनता को कुछ ऐसे मसलों का सामना करना पड़ा जो बड़े और पेचीदा थे । मगर तरह-तरह की कठिनाइयों और रुकावटों के बावजूद हम अपने लक्ष्य की तरफ बराबर बढ़ते रहे हैं, जो यह रहा है कि अपने देश में हम लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवादी समाज की स्थापना करें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शान्ति और सहयोग बनाए रखें ।

३. हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना ने तीन वर्षों में जो प्रगति की है उसका मूल्यांकन करने पर योजना कमीशन को पता चला है कि बाकी के दो वर्षों में बहुत बड़ी मंजिल तै करनी है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हों तो हम को जी-जान से कोशिश करनी पड़ेगी ।

४. दोबारा मूल्यांकन करने पर यह जरूरी था कि हम उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देते जिनमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से पीछे रह गए हैं लेकिन इसके माने यह कभी नहीं है कि जो प्रगति हमने की है या जो सफलता हमें मिली है उसे हम कम करके देखें या उसकी तरफ से आंखें फेर लें । औद्योगिक उत्पादन बराबर बढ़ता रहा है । ऐसी आशा की जाती है कि पिछले साल जितना औद्योगिक उत्पादन हुआ था, १९६३-६४ में उससे ७-८ प्रतिशत अधिक होगा । कोयला और इस्पात जैसे बुनियादी उद्योगों में और प्रगति हुई है । इस्पात के कारखाने लगभग पूरी ताकत से उत्पादन कर रहे हैं । देश के कुछ भागों में जरूर बिजली

की कमी महसूस की गई है लेकिन कुल मिला कर ज्यादा बिजली पैदा की गई है और परिवहन की कठिनाइयां भी कम हुई हैं । निर्यात से हमारी आमदनी बढ़ी है और हमारे मित्र देश हमें जो बाहरी सहायता देते रहे हैं उससे हमारे विदेशी मुद्रा-कोष की हालत सुधरी है और देश को जो अदायगियां करनी हैं उनके कारण पिछले साल उस पर जितना दबाव पड़ रहा था इस साल नहीं पड़ रहा है ।

५. पब्लिक सेक्टर के प्रतिष्ठानों ने अच्छी-खासी तरक्की की है । १६ नवम्बर, १९६३ को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत में बना पहला ए० सी० बिजली का इंजन चालू किया । भोपाल के हैवी एलेक्ट्रिकल प्लांट का उत्पादन बढ़ गया है । नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने किरीबूरु की लोहे की खानों का विकास करीब-करीब पूरा कर लिया है । आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन ने गुजरात में तेल और गैस के काफ़ी बड़े जख़ीरों का पता लगा लिया है । ट्रांबे के एटमिक एनर्जी इंस्टेबलिशमेंट ने रेडियो आइसोटोप्स का निर्यात करना शुरू कर दिया है ।

६. कई ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जिनको अमल में लाने की दर्ज-ब-दर्ज तैयारियां हो रही हैं और इनसे आने वाले वर्षों में हमारी आर्थिक व्यवस्था को नई शक्ति मिलेगी । पब्लिक सेक्टर के तीन इस्पात के कारखानों को और बड़ा करने की योजना चल रही है । दुर्गापुर के अलाय एण्ड टूल स्टील प्लांट में काम हो रहा है । बोकारों में इस्पात का कारखाना खोलने के काम की शुरुआत कर दी गई है । तारापुर और राना प्रताप सागर, राजस्थान, में एटमी शक्ति के स्टेशनों को स्थापित करने के लिए क्रमशः संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा से करार किए जा चुके हैं । जब कुछ और ऐसे कारखाने बन कर तैयार हो जायेंगे, जिनके लिए जरूरी विदेशी सहायता ली जा चुकी है, तब हम अपनी तीसरी पंच वर्षीय

[प-राष्ट्रपति]

योजना के लक्ष्य से बहुत पीछे न रहेंगे। साथ ही हमारी चौथी योजना के शुरू के वर्षों में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ और बिजली के कारखाने खोलने के सम्बन्ध में पहले से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

७. ये बातें संतोषजनक हैं, फिर भी हमारा आर्थिक विकास उस गति से नहीं हो रहा है जो हमारा योजना का लक्ष्य था। इसकी खास वजह है खेती की पैदावार का घटना, जो १९६२-६३ में ३.३ प्रतिशत कम हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खेती को यके-बाद-दीगरे खुराब मौसम का सामना करना पड़ा है। हमारे सामने आज सबसे जरूरी काम यह है कि खेती की पैदावार को बराबर बढ़ाया जाय।

८. तीसरी योजना के पहले दो सालों में खेती के काम को बढ़ाने के लिए बराबर कोशिश की गई है। लगभग ६० लाख एकड़ नई जमीन को सिंचाई की सुविधा पहुंचाई गई है। कोशिश हो रही है कि चालू वर्ष में इसके अलावा ५५ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा दी जाय। छोटे पैमाने की सिंचाई, भूमि-संरक्षण और खेती की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को १९.१५ करोड़ रुपए और दिए गए हैं।

९. गल्ले की पैदावार में जो कमी आई है उसका कीमतों के स्तर पर बढ़ा असर पड़ा है। सरकारी गोदामों से ज्यादा गल्ला निकाल कर, जहां मुमकिन था, सस्ते अनाज की और ज्यादा दुकानें खोल कर, गल्ले को ठीक जगह पर पहुंचा कर, और उधार देने की नीति बरतकर, हर तरह कोशिश की गई है कि गल्ले का दाम चढ़ने न पाये। अप्रैल-१९६३ से फेब्रुरी से निकलने पर चीनी के दाम तथा उसके वितरण पर फिर से कंट्रोल लगा दिया गया है।

१०. जो बात खेती की पैदावार के लिये अच्छी कही जा सकती है वही औद्योगिक

उत्पादन के लिए भी ठीक है कि आखिर में चल कर दामों में ठहराव तभी आयेगा जब पैदावार इतनी बढ़ जाय कि उस से बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके। खेती के क्षेत्र को मजबूत बनाने और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो उपाय हम ने किए हैं, उन का जिक्र मैं ने किया। इन तथा दूसरे उपायों से, साथ ही खेती की खास-खास फसलों का भाव ठीक रखने की नीति से, ऐसा समझा जाता है कि खेती की पैदावार भी बढ़ेगी और उत्पादन उता भी।

११. औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिये कई तरह के प्रशासन सम्बन्धी परिवर्तन किये गए हैं, काम करने के तरीकों को आसान किया जा रहा है, और कुछ कंट्रोलों में ढील दे दी गई है। खेती और उद्योग के लिए, खास कर सहकारी क्षेत्र और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये, आर्थिक सहायता बढ़ाई जा रही है।

१२. प्रशासन के काम में चुस्ती लाने के लिए और भ्रष्टाचार और बर्बरता के खिलाफ की गई शिकायतों पर फौरन और कारगर ढंग से ध्यान देने के लिये यह तैयारी किया गया है कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमिशन की स्थापना की जाय जिस का दर्जा, अपने क्षेत्र में, लगभग वैसा ही होगा जैसा कि यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कमिशन का है। इस की सालाना रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाया करेंगी।

१३. जुलाई १९६३ में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी की यूनिवर्सल टैरिटरी में विधान सभायें और मंत्रि-परिषदें बनाई गयीं, और पिछली दिसम्बर में गोवा, दमन, दीव में भी इसी तरह की सभा और परिषद् की स्थापना हुई। १ दिसम्बर, १९६३ को नागालैंड राज्य बनाया गया और जनवरी, १९६४ में उसकी विधान सभा के लिए चुनाव किए गए।

१४. हालांकि हमारी सीमा पर लड़ाई तो नहीं हुई, फिर भी सारे साल चीन से खतरा बना रहा। कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में चीन अभी तक अपना जिद्दी रवैया बनाए हुए है और उम ने हमारी सीमाओं पर अपनी फौजी शक्ति बढ़ाई है।

१५. हम शान्ति के कायल हैं और इस नीति के भी कि संसार के तमाम झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाय, फिर भी हम अपने बचाव की तरफ से गाफिल नहीं हो सकते। इस वर्ष के दौरान हमारी फौज और हवाई सेना को सुधारने और बढ़ाने के लिये बहुत से कदम उठाए गए। हमारी हथियारबंद फौजों की सभी शाखाओं में रंगरूटों की भर्ती संतोषजनक रही है लेकिन तकनीकी सेवाओं में काम करने वाले योग्य आदमियों की कमी महसूस की जा रही है। सेना में काम करने वालों की नौकरियों की शर्तों में बहुत से सुधार किए गए हैं। जो बड़े-बड़े उपाय किये गये हैं वे ये हैं : कमीशन-प्राप्त अफसरों की पेंशन दरों में संशोधन, अफसर-इज से निचले दर्जे के जो कर्मचारी मर गए हों, उन की विधवाओं और उन पर निर्भर लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचाने में उदारता और छोटी रकम की पेंशनों में बढ़ोतरी।

१६. हमारी सेनाओं को साज-सामान से लैस करने की दिशा में हमें संयुक्त राज्य-अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल के कई देशों ने काफी मदद दी है और आगे और भी साज-सामान आने को है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार ने हमें कई सामान इंग्राने वाले हवाई जहाज और अन्य उपकरण दिये हैं और वे हमारे देश में आवाज की गति से तेज चलने वाले हवाई जहाज तैयार करने का कारखाना बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन देशों से हमें जो सहायता मिली है, उस के लिए हम उन के आभारी हैं।

१७. हमारी रक्षा सेनाएं साज-सामान से पूरी तरह लैस हैं, इस के लिए हम
 1987 (Ai) LSD.—3

चाहते हैं कि उस का ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादन हमारे ही देश में हो। हमारी रक्षा के लिए विदेशों में जिस सहायता की व्यवस्था है, उस के अन्तर्गत जरूरी प्लांट और मशीनें मंगा कर हम सामरिक उद्योगों में उत्पादन का आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। १९६३-६४ में आर्डेन्स फैक्टरियों में १०० करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन होने की आशा है, जबकि १९६२-६३ में यह उत्पादन ६३ करोड़ का था और १९६१-६२ में ४१.४५ करोड़ रुपये का।

१८. अपनी घोषित नीति के अनुसार, हम दुनिया के तमाम देशों के साथ मित्रता और सहयोग का सम्बन्ध रखने की कोशिश करते रहे हैं। साथ ही अपन्नी शांतिपूर्ण सह-जीवन और गुटों से अलग रहने की नीति का भी पालन किया है। हमारी इस नीति का समर्थन और उस की सराहना कई अन्तर-राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों ने की है।

१९. हमारे राष्ट्रपति जी को संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, नैपाल, अफगानिस्तान और ईरान जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन की सरकारों और वहां के लोगों का प्रेम-पूर्ण स्वागत-सत्कार पाकर उन्हें बड़ी खुशी हुई है। सद्भाव और मित्रता को और बढ़ावा देने की गरज से, मैंने इथोपिया, सूडान और संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की। इसके अलावा, हमारे कई मंत्रियों और अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने इसी भावना से संसार के कई देशों का दौरा किया।

२०. इस वर्ष के दौरान हमारी सरकार को जिन सम्मानित अतिथियों के भारत आने पर उनका स्वागत-सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे ये हैं : महामहिम लाओस

[उप-राष्ट्रपति]

नरेश, महामहिम नेपाल नरेश और उनकी महारानी, जोर्डन के महामहिम शाह, साइप्रस गणराज्य के उप-राष्ट्रपति, संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यकारिणी परिषद् के प्रधान, सोमाली गणराज्य के प्रधान मंत्री, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य मंत्री, न्यू साउथ वेल्स के मुख्य मंत्री, संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री, अर्ल माउंटबेटन आफ बर्मा, डेन्मार्क की राजकुलमान्या राजकुमारी मार्गरेट और सोवियत अंतरिक्ष यात्री वलेन्तीना तेरेशकोवा निकोलायवा और उन के दो साथी ।

२१. प्रेसीडेंट केनेडी की हत्या का समाचार सुनकर हमें बड़ा सदमा पहुंचा और दुःख हुआ । उनकी मृत्यु से भारत ने एक सच्चा मित्र खोया और दुनिया ने अमन और दोस्ती का ज्वरदस्त हिमायती । हम प्रेसीडेंट जॉनसन के इस एलान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वे तनाव कम करने और दुनिया में अमन बनाए रखने के अहम और मुश्किल काम में स्वर्गीय प्रेसीडेंट केनेडी की नीति का ही पालन करेंगे ; साथ ही उन देशों के आर्थिक विकास में सहयोग भी देंगे जो कम विकसित हैं ।

२२. अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो अति उत्साह वर्धक घटनाएं हुई हैं उनमें से एक यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ ने बाहरी अंतरिक्ष में एटमी हथियारों पर रोक लगाने के सिद्धान्त को मंजूर कर लिया है । इसे बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार कर लिया है । यह घटना और परीक्षण रोकने का करार निरस्त्रीकरण करने और सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में पहले अहम कदम है, जिन्हें उसी वातावरण में हासिल किया जा सकता है जिसमें एक-दूसरे पर भरोसा किया जा सके और एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा जा सके । चेयरमैन ध्युश्चेव ने प्रदेश या सीमा के झगड़ों को तय करने में शक्ति का

प्रयोग न करने के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय करार करने का जो प्रस्ताव किया है, उसमें निहित सिद्धान्त से हम मंटे तीर पर सहमत हैं, और आशा करते हैं कि जिन प्रमुख राष्ट्रों का इनसे सरोकार है, व परस्पर विश्वास की भावना से इस अहम मुद्दा पर एक ऐसा समझौता कर सकेंगे जो सबके लिए संतोषजनक हो और सबको मंजूर हो ।

२३. नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही मजबूत और मित्रतापूर्ण हैं और दोनों देश एक-दूसरे की समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरी तरह समझते हैं और उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं । हम भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबर मदद दे रहे हैं ।

२४. महाराजा सिक्किम की मृत्यु से भारत और सिक्किम, दोनों को जो ज्वरदस्त सदमा पहुंचा वह संसद् के सदस्यों से छिया नहीं है । उनके सुपुत्र, राज्यमान्य पाल्देन थोंडुप नामग्यल दिसम्बर १९६३ में गद्दी पर बैठे ।

२५. हमें इस बात की खुशी है कि कुवैत को संयुक्त राष्ट्र में वह स्थान मिल गया है जिसका कि वह हकदार है । कीनिया और उगांडा की आजादी पर हमें खुशी है और इस पर भी कि अफ्रीका के दूसरे देश जल्द आजाद होने का हैं । हम चाहते हैं कि इन देशों के साथ हमारा सम्बन्ध ज्यादा से ज्यादा नजदीकी हो और हम विकास के उन बहुत से कार्यभारों में भी उनका हाथ बटा सकें जो नए आजाद मुल्कों को उठाने पड़ते हैं ।

२६. हमें उन अफ्रीका निवासियों के साथ पूरी हमदर्दी है और हम उनकी पूरी हिमायत करते हैं जो अब भी पुर्तगाल की उपनिवेशी हकूमत में हैं और आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं । अफ्रीका और दुनिया के दूसरे मुल्कों के उन लोगों के साथ भी हमारी हमदर्दी है और हम उनकी हिमायत करते हैं जो दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग और जातिभेद की नीतियों को खत्म कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं ।

२७. जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान की मंशा समझौता करने की कतई नहीं है। "कश्मीर और उससे जुड़े हुए दूसरे मसलों" पर दिसम्बर १९६२ में मंत्रियों के स्तर पर बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह पांच दौरों के बाद १६ मई १९६३ को कटु वातावरण में टूट गया। सच तो यह है कि इस बातचीत के सफल होने की आशा तो तभी टूट गई थी जब पाकिस्तान ने चीन के साथ सीमा-समझौता करके कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया था जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था। इसके बावजूद और भारत के खिलाफ चीन के साथ सांठ-गांठ करने की दूसरी कारिस्तानियों के बावजूद भी, हमारी सरकार धीरे-धीरे के साथ बातचीत करती रही लेकिन इस बातचीत के पांचों दौरों ने यह बात साफ़ कर दी कि पाकिस्तान तर्क और तथ्य के आधार पर समझौता करना नहीं चाहता और इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ़ यह है कि उसे भारत के खिलाफ़ प्रोपेगैंडा करने का मौक़ा मिल जाय।

२८. इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद, भारत-पाकिस्तान की समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का रास्ता भारत खोजता रहा, और जहाँ तक हो सका, उसने पाकिस्तान द्वारा चलाए 'भारत से नफ़रत' के आन्दोलन को भी नज़रअन्दाज़ किया। हमारे प्रधान मन्त्री ने एक बार फिर यह अपील की कि भारत और पाकिस्तान के बीच 'जंग न करने का ऐलान' किया जाय और साथ ही भारत और पाकिस्तान के सभी झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करने की कोशिश की जाय। लेकिन प्रधान मन्त्री की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और साल के ख़त्म होते-होते भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध उससे भी कहीं ज्यादा खराब हो गए जितने कि वह १९६२ में थे।

२९. दिसम्बर १९६३ के आखिरी हफ़्ते में कश्मीर के कुछ समाज-विरोधी लोगों ने 'हज़रतबल' की दरगाह से मूएमुबारक चुराकर जो घोर अपराध किया उस से कश्मीर और बाकी भारत के लोगों को बहुत चिन्ता हुई। लेकिन कश्मीर के अधिकारियों की सहायता करने में हमारी सरकार ने बड़ी भुर्ती से कार्रवाई की जिसके कारण पवित्र बाल मूए मुबारक मिल गया और इससे समूचे भारत के लोगों को बड़ी खुशी हुई और राहत मिली। परन्तु पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस दुर्घटना का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में भारत-विरोधी और फ़िरकापरस्ती की भावना फैलाई जिसका नतीजा यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में कई जगहों में, जिसमें कि ढाका भी शामिल था, जोर के दंगे हुए, क़ानून और इन्तज़ाम ख़त्म हो गया और उसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति के कई सौ आदमी मार डाले गए और उनकी सम्पत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के कुछ दूसरे इलाकों में इन दुर्घटनाओं का बुरा असर पड़ा, लेकिन सरकार ने बलवाइयों के खिलाफ़ बड़ी तेज़ी और सख्ती से कार्रवाई की और, जाति-धर्म का ख़्याल किए बिना, भारत के सभी नागरिकों के जान-माल की पूरी हिफ़ाज़त की। हमारे राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव भी रखा कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिल कर दोनों देशों में रहने वाली विभिन्न जातियों से मेल-मिलाप और शांति से रहने की अपील करें उन्होंने इस अपील पर कार्रवाई करने के कुछ अमली तरीके भी सुझाए लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इन सुझावों को मानने से इंकार ही किया है। पूर्वी पाकिस्तान में जो दंगे हुए उनमें वहाँ के विभिन्न इलाकों में रहने वाली अल्पसंख्यक जाति के लोगों की जान और माल का भारी नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे सामने पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक जाति के लोगों के भारत आने की समस्या खड़ी हो गई है

[उप-राष्ट्रपति]

३०. संसद् सदस्यगण ! मैंने आप लोगों के सामने पिछले वर्ष देश की खास-खास कामयाबियों और मसलों का एक ब्यौरा रखा। हमें जो काम करने हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उनका एक छोटा-सा खाका भी मैंने आपके सामने पेश किया है। इन पर आप अच्छी तरह गौर करें, इन्हें समझें और इन्हें पूरा करने और निभाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। हमारी सरकार हर तरह से अपने देश और देश के निवासियों की आजादी और इज्जत को बनाये रखने की, देश में एकता और खुशहाली बढ़ाने की, और एक ऐसा लोकतन्त्रीय और समाजवादी समाज बनाने की, कोशिश करती रहेगी जिसमें शान्तिपूर्ण तरीकों से और सबकी रजामन्दी से प्रगति की जा सके।

३१. १९६३ के दौरान ससद् ने ५८ बिल पास किए थे। १९ पिछले बिल अभी बाकी हैं जिन पर आपको विचार करना है। विचार के लिए जो बिल आप के सामने रखे जाएंगे उनमें ये भी शामिल होंगे :—

- (१) कम्पनी (संशोधन) बिल।
- (२) भारतीय फ़सल बीमा बिल।
- (३) भार एवं माप-मानक (संशोधन) बिल।
- (४) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) बिल।
- (५) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, १९२५ को खत्म करने और कुछ संशोधन के साथ पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, १९६१ दिल्ली में लागू करने से सम्बद्ध बिल।
- (६) विदेशी मुद्रा नियमन (संशोधन) बिल।
- (७) संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) बिल।

(८) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल।

(९) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल।

३२. भारत सरकार के १९६४-६५ के माली साल की आमदनी और खर्च के अंदाजे का ब्यौरा आपके सामने रखा जायगा।

३३. संसद् सदस्यगण ! मेरी कामना है कि आपको अपने कार्य में सफलता मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि विवेक, सहनशीलता और सहयोग की भावना से आप लोग काम करते रहेंगे। मेरी शुभकामना है कि आपके प्रयत्नों से हमारे देशवासियों को अधिकाधिक सुख और सन्तोष प्राप्त हो, हमारी मातृभूमि सुस्थिर और सुरक्षित रहे और संसार में शान्ति और सहयोग की भावना समृद्ध हो।

Address

Vice-President: Members of Parliament, I am happy to welcome you once again to your labours in a new session of Parliament.

2. In the year which has just ended, the Government and the people of India have had to face problems which were vast in magnitude and complex in character. In spite of difficulties and distractions, we have continued to move forward towards our objective of a democratic and socialist order at home and for peace and co-operation in international affairs.

3. The mid-term appraisal of our Third Five-Year Plan undertaken by the Planning Commission has revealed that the ground to be covered in the remaining two years is considerable and an all-out effort would be required to realise our expectations.

4. While attention in the re-appraisal has necessarily been focussed on the sectors where we seem to be lagging behind the targets which had been set, it is important not to overlook or minimise the progress that

has been made and the achievements which are in sight. The upward trend in industrial production has been maintained. The general level of industrial output in 1963-64 is expected to be 7 to 8 per cent higher than in the previous year. Basic industries, like coal and steel, have made further progress and production in the steel plants is running at near capacity. While, power shortages have been felt in certain parts of the country, the total availability of power has improved and the transport position is easier. There has been an improvement in export earnings and with continuing external assistance from friendly countries, our foreign exchange reserves and the country's balance of payments position have not been under the same kind of pressure as in the previous year.

5. Public sector undertakings have made significant progress. The first Indian-manufactured A. C. electric locomotive rolled out of the Chittaranjan Locomotive Works on November 16, 1963. The Heavy Electrical Plant at Bhopal has increased its output. The National Mineral Development Corporation has practically completed the development of Kiriburu iron ore mines. The Oil and Natural Gas Commission has established the existence of substantial reserves of oil and gas in Gujarat. The Atomic Energy Establishment at Trombay has begun exporting radio isotopes.

6. A number of new projects are in various stages of implementation and will add fresh strength to our economy in the years ahead. The expansion schemes of the three public sector steel plants are well under way. Work on the Alloy and Tool Steel Plant at Durgapur is in progress. Action has been initiated for the setting up of the steel plant at Bokaro. Agreements have been signed with the United States of America and with Canada for the setting up of atomic power stations at Tarapore and Rana Partap Sagar in Rajasthan

respectively. With the other plants under construction for which the necessary external assistance has already been secured, we shall not be far short of our Third Plan target and advance action on additional power plants to take care of our needs in the early years of the Fourth Plan has been initiated.

7. Despite these satisfactory trends, the overall rate of economic growth has lagged behind the Plan target. This is mainly due to the shortage in agricultural production which in 1962-63 showed a fall of 3.3%. There have been successive bad agricultural seasons in the course of the Third Five-Year Plan. A steady increase in agricultural production is the most important task before us today.

8. There has been a steady expansion in the overall agricultural effort during the first two years of the Third Plan. About six million acres of additional area have been brought under irrigation. Efforts are being made to extend irrigation facilities to over 5.5 million acres during the current year. Additional allocations of Rs. 19.15 crores have been made to the States for stepping up minor irrigation, soil conservation and agricultural production.

9. Shortfalls in the production of foodgrains have had a disturbing effect on price levels. Through larger releases of foodgrains from Government stocks, the setting up of additional fair-price shops wherever feasible and appropriate regulation of movements, and through credit policies, every effort has been made to prevent prices of foodgrains from shooting up. Control over the ex-factory price and distribution of sugar was reimposed in April, 1963.

10. In the long run, however, the stability of prices, whether of agricultural or industrial products, can only be achieved through higher production to match the rising level of consumption. I have referred to some of the measures which we have taken

[Vice-President]

to strengthen the agricultural sector and increase agricultural production. These and other measures, together with the policy of price support for major agricultural crops, should raise the levels of production and productivity in agriculture.

11. To accelerate the pace of development in industry, various administrative changes have been introduced, procedures are being simplified and certain controls have been relaxed. Finance, both for agriculture and industry, particularly the co-operative sector and small-scale industries, is being made available on an increasing scale.

12. To improve the tone of administration and to deal effectively and promptly with complaints of corruption or lack of integrity, it has been decided to set up a Central Vigilance Commission which will have a status in its own sphere broadly corresponding to that of the Union Public Service Commission. Its annual reports will be placed before both Houses of Parliament.

13. Legislative Assemblies with Councils of Ministers were constituted in July, 1963, in the Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Pondicherry and a similar set up was established in the territories of Goa, Daman and Diu in December last. The State of Nagaland was formed on December 1, 1963, and elections to the Legislative Assembly were held in January, 1964.

14. The Chinese threat has continued throughout the year, though there has been no actual fighting along our borders. China still maintains its intransigent attitude on the Colombo proposals and Chinese military build-up along our borders has increased.

15. Dedicated as we are to peace and to the policy of peaceful settlement of all international disputes, we cannot afford to neglect our defences.

During the course of the year, many steps were taken to improve and expand our Army and Air Force. The response to our demand for recruits to the Armed Forces has been satisfactory in all branches, but we are facing a dearth of qualified personnel for our Technical Services. The conditions of service of armed personnel have been improved in many ways. The more important measures include revision in the rates of pension of Commissioned Officers, liberalisation of pensionary benefits to widows and other dependents of deceased personnel below officer rank and *ad hoc* increases in small pensions.

16. In the matter of equipping our Forces, appreciable assistance has already been received from the Governments of the United States, the United Kingdom and a number of Commonwealth countries and further assistance is on its way. The Government of the U.S.S.R. have supplied us with a number of transport aircraft and other equipment and are assisting us in establishing a supersonic aircraft factory in the country. We are grateful to all these countries for the help they have extended to us.

17. To keep our Defence Forces well-equipped, we are anxious to rely on domestic production to the maximum possible extent. We are trying to secure a strengthening of our production base for strategic industries by getting the necessary plant and machinery under the external assistance provided for our Defence. Production in the Ordnance Factories in 1963-64 is expected to exceed Rs. 100 crores as compared with Rs. 63 crores in 1962-63 and Rs. 41.45 crores in 1961-62.

18. In accordance with our declared policy, we have continued to seek friendly and co-operative relations with all countries in the world and we have been adhering to the policy of non-alignment and peaceful co-existence, which is receiving grow-

[Vice-President]

26. We extend our full sympathy and support to the African people who are still under Portuguese colonial rule in their struggle for freedom and independence and in the efforts being made by all people of Africa and other countries of the world to put an end to the policies of apartheid and racial discrimination practised by the Government of South Africa.

27. As regards our relations with Pakistan, I regret to say that there has been no desire on the part of Pakistan to reach any settlement. The Minister-level discussions on "Kashmir and other related matters" that began in December, 1962, broke up after five rounds of talks on May 16, 1963, on an acrimonious note. Hopes for the success of these talks were, in fact, shattered by Pakistan concluding a border agreement with China ceding to China a large area of Kashmir which was under Pakistan's military occupation. In spite of this and other acts of collusion with China against India, our Government patiently pursued the negotiations, but the five rounds of talks clearly showed that Pakistan has no intention to reach a settlement on a rational and realistic basis and that its sole object in entering into these bilateral discussions was to gain propaganda advantage against India.

28. Despite these unfortunate developments, India continued to seek avenues for peaceful solution of Indo-Pakistan problems and to ignore, as far as was possible, the "Hate India" campaign that had been mounted in Pakistan. A renewed call was made by our Prime Minister for a "No War Declaration" between India and Pakistan, and for simultaneous efforts to solve Indo-Pakistan differences through peaceful methods. The Prime Minister's appeal was disregarded and the year ended with Indo-Pakistan relations in a far worse condition than during 1962.

29. The heinous sacrilege committed by some anti-social elements in Kashmir who stole the holy relic from

the Hazratbal shrine in the last week of December, 1963, caused serious concern to all people in Kashmir as well as the rest of India. The prompt action taken by our Government in assisting the local authorities in Kashmir in the investigations resulted in the recovery of the holy relic which was a matter of great joy and satisfaction to people all over India. The Pakistan authorities, however, exploited this incident to fan anti-Indian and communal feelings in Pakistan which led to serious disturbances and complete breakdown of law and order in various areas of East Pakistan including Dacca itself, resulting in the loss of several hundreds of lives of the minority community in East Pakistan and considerable loss of property belonging to the minority community. These incidents had repercussions in Calcutta and certain areas of West Bengal and Government took prompt and firm action against the miscreants and gave full protection to the life and property of all citizens of India, irrespective of their caste or creed. Our President also made a proposal for a joint appeal by the Presidents of India and Pakistan to restore peace and harmony amongst the various communities living in the two countries and suggested certain practical steps to follow up this appeal. Pakistani response to these proposals has so far been negative. The disturbances in East Pakistan have taken a heavy toll of the lives and properties of the members of the minority community in various areas of East Pakistan. As a result, we are faced with a large influx of the members of the minority community from East Pakistan into India.

30. Members of Parliament, I have placed before you an account of our main achievements and problems of the past year. I have also given you a brief picture of the tasks and burdens that face us. They need your dedicated attention, understanding and co-operation in increasing measure. It will continue to be the endeavour of

our Government, in all possible ways, to uphold the dignity and independence of our land and people, to promote our unity and well-being and to build a democratic and socialist society in which progress is sought and attained by peaceful means and by consent.

31. Fifty-eight Bills were passed by Parliament during 1963. Nineteen Bills are pending before you. Among the Bills that will be placed before you for your consideration will be:—

(1) The Companies (Amendment) Bill.

(2) The Indian Crop Insurance Bill.

(3) The Standards of Weights and Measures (Amendment) Bill.

(4) The Indian Railways (Second Amendment) Bill.

(5) Bill to repeal the Bombay Co-operative Societies Act, 1925, as applicable to the Union Territory of Delhi and to extend the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, with certain modifications to Delhi.

(6) The Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill.

(7) The Constitution (Eighteenth Amendment) Bill.

(8) The Banaras Hindu University (Amendment) Bill.

(9) The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill.

32. A statement of Estimated Receipts and Expenditure of the Gov-

ernment of India for the financial year 1964-65 will be laid before you.

33. Members of Parliament, I wish you success in your labours. I earnestly trust that wisdom and tolerance and a spirit of co-operative effort will guide you. May your endeavours bring increasing prosperity and contentment to our people, stability and security to our Motherland and assist in promoting peace and co-operation in the world.

LEGAL TENDER (INSCRIBED NOTES) BILL*

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to restrict the negotiability of currency and other notes inscribed with messages of a political character.

Mr. Speaker: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to restrict the negotiability of currency and other notes inscribed with messages of a political character.”

The motion was adopted.

Shri T. T. Krishnamachari: Sir, I introduce the Bill.

12.22 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 11, 1964/Magha 22, 1885 (Saka).

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 10-2-1964.

†I introduced with the recommendation of the President.